Sr. No.	**Announcement Para/Description (Year 2023-24)**
1	11.02.00 (2023-2024) 10/02/2023 परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी identification सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जायेगा ।
2	18.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 iStart Fund के माध्यम से Startups को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा।
3	19.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 प्रदेश में युवाओं को अपना Startups स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ रुपये की लागत से- I. ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों/ महाविद्यालयों में iStart लॉन्चपैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जायेगा । II. Rajiv Gandhi Innovations Challenge के अन्तर्गत प्रथम award की राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिये जाने प्रस्तावित । III. जनजाति क्षेत्र के युवाओं हेतु गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में Incubation and Innovation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
4	104.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 शहरी विकास को नए आयाम तक ले जाने एवं शहरों को 'Smart' बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। वर्तमान में जयपुर शहर की प्रभावी प्लानिंग, प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु '3D City' परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसी क्रम में जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित '3D City' परियोजना की घोषणा। इसके लिए 300 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
5	135.02.0 (2023-2024) 10/02/2023 आगामी वर्ष में प्रदेश के कोने-कोने में आमजन विशेषकर महिलायें सुरक्षित महसूस कर सकें, इस हेतु CCTV कैमरों की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 5 लाख की जायेगी।
6	135.04.0 (2023-2024) 10/02/2023 आगामी वर्ष में अभय कमांड सेंटर के तकनीकी सिस्टम को upgrade करते हुए, प्रदेश के Command Centres की call taking क्षमता बढ़ाने के लिए कुल सीटों को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 125 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
7	141.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 नीति निर्धारण के साथ ही सेवा प्रदायगी में IT का प्रयोग कर सुशासन स्थापित करने में राजस्थान देश में आज Pioneer के रूप में जाना जाता है। नवाचारों के इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देश में सम्भवतः पहली बार पात्र व्यक्ति / परिवारों को बिना आवेदन किये ही घर बैठे auto benefits व सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सके. इसके लिए जन आधार data base का उपयोग करते हुए Information Technology. Artificial Intelligence व Machine Learning आधारित Real Time Auto Service Delivery System-SWATAH (स्वतः) लागू किये जाने की घोषणा। इस प्रणाली की विशेषता है कि इसके माध्यम से विभिन्न सेवाएं स्वतः उपलब्ध हो जायेंगी, जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाना, NFSA पात्रता व आयु के आधार पर स्वतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत होना तथा जन आधार व शालादर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति / पालनहार स्वतः उपलब्ध होना।
8	142.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 IT हेतु आवंटित किए जाने वाले बजट का 5 प्रतिशत भाग cyber security के लिए खर्च किया जाना प्रस्तावित है। यह निर्णय देश में ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

9	142.02.0 (2023-2024) 10/02/2023 सरकारी Land Records, Health Records, e- Coupons में भी किसी प्रकार के manipulations की रोकथाम के लिए इन रिकार्ड्स को Block Chain Technology द्वारा सुरक्षित संधारित किया जायेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
10	142.03.0 (2023-2024) 10/02/2023 जयपुर में Rajiv Gandhi Centre for IT Development and e-Governance स्थापित किया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।
11	143.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं सुलभ कराने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि कार्यालय प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी सरल किया जाये। सचिवालय सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में e-office प्रणाली लागू कर दी है। इसी कड़ी में, विभागों / PSUs / बोर्ड / निगम कार्यालयों में process re-engineering करते हुए files पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से मोबाइल मेसेजिंग, डाटा एनालिटिक्स, प्रोसैस ऑटोमेशन, Artificial Intelligence आदि नवीनतम तकनीक आधारित RajKaj 2.0 विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
12	144.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 सुशासन हेतु यह भी आवश्यक है कि नीति निर्माण evidence based हो, उसमें behavioural science का उपयोग किया जाये तथा सरकारी योजनाओं का concurrent evaluation हो, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में real time में ही सुधार किया जा सके। इसके लिए Integrated Data Analytics System 'PARAM' विकसित किया जायेगा। साथ ही, समस्त Data के storage हेतु Centralised Data Lake बनाया जायेगा। इन पर 85 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
13	145.00.0 (2023-2024) 10/02/2023 शहरी नियोजन Forest Survillence, आपदा प्रबन्धन, कृषि, पर्यटन, खान एवं भूविज्ञान आदि विभागों में ड्रोन की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 450 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार ड्रोन मय पायलट उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।
14	146.01.0 (2023-2024) 10/02/2023 आगामी वर्ष अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालयों पर RCAT केन्द्र खोले जायेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है।
15	199.05.0 (2023-2024) 10/02/2023 स्टार्ट-अप से बिना टेंडर उपापन (Single Source Procurement) की वर्तमान 15 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा।
16	272.01.02 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 प्रदेश में शिक्षण एवं अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को spoken english, administration एवं leadership development के लिए training दी जायेगी।
17	272.02.03 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉक मुख्यालयों पर स्कूलों/कॉलेजों में 20 करोड़ रुपये की लागत से English Language Labs की स्थापना की जायेगी। इससे 50 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
18	277.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 विद्यार्थियों एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में iStart Innovation School Hub की स्थापना की जायेगी।
19	290.00.02 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) तथा मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगीभार को देखते हुए मरीजों को सुगमता से समस्त चिकित्सा

	सुविधायें देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री ट्रेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित Integrated Health Management System (IHMS) को सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रभावी किया जायेगा। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) तक क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।
20	315.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 राज्य के रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्वस तथा जवाई बांध-पाली और झालाना नेचर पार्क-जयपुर लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्वस में वर्तमान Wildlife Survillence and Anti-Poaching System (WS & APS) को मजबूत करने के साथ-साथ रामगढ़ विषधारी-बूंदी, जमवारामगढ़ अभ्यारण्य-जयपुर, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य-राजसमंद-उदयपुर -पाली, टॉडगढ़ रावली-अजमेर-राजसमंद-पाली आदि वन क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जायेगा। इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
21	337.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 16/02/2023 योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म 'Raj Dhara' का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस क्रम में विभिन्न विभागों हेतु सेटेलाइट इमेजरी की आवश्यकताओं के अनुरूप राजधारा प्लेटफॉर्म पर Time Series High Resolution Satellite Imagery Repository की स्थापना की जायेगी एवं इसके विश्लेषण हेतु High-end Lab की भी स्थापना की जायेगी, जिससे राज्य के विकास एवं आवश्यकताओं की प्रभावी समीक्षा की जा सकेगी। इसके लिए 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
22	418.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 17/03/2023 आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवायें उपलब्ध करवाने तथा कार्यालयों में होने वाली Work Processing को IT के माध्यम से Online करने में आज प्रदेश सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित IT Softwares का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रदेशवासियों को मिल सके, इस हेतु ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी, तहसीलदार/विकास अधिकारी से लेकर जिला प्रमुख/कलक्टर आदि तक Tablet देने का निर्णय किया था। अब इसी क्रम में, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्यों एवं दायित्वों के बेहतर निष्पादन हेतु Laptop/Tablet दिया जाना प्रस्तावित है।
23	419.00.0 (2023-2024) Hon'ble CM Reply on 17/03/2023 प्रदेश के इस विकसित IT तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से गत बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय Internet Connectivity उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस निर्णय के पश्चात् अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर Smart Phone/ Automobiles में प्रयोग किये जाने वाले Chipset की crises उत्पन्न हो गयी थी। इस कारण Smart Phone की उपलब्धता की समस्या के साथ ही कीमतों में भी वृद्धि हो गयी। फिर भी हम इस कार्य को अब चरणबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे। आगामी वर्ष बहन-बेटियों के पावन पर्व 'राखी' से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/ ITI/ Polytechnic) में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजनान्तर्गत यह Smart Phone उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस प्रकार प्रारम्भिक चरण में लगभग 40 लाख लाभान्वितों को यह Smart Phone प्राप्त हो सकेंगे।